



'पाकिस्तान की सेना सुनियोजित तरीके से प्रजातंत्र को खत्म कर रही है'

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो जेल में हैं, ने एक वक्तव्य जारी करके यह कहा है कि "पाकिस्तान की सेना ने चुनाव जीत कर आयी सरकारों को केवल एक "रबड़-स्टाम्प" संस्थान बना दिया है, जिसे वे "रिमोट कंट्रोल" से चलाते हैं"

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मई। पाकिस्तान के

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो वर्तमान

में जेल में हैं और जिनके द्वारा लड़ने पर

प्रतिबंध लगा हुआ है, ने एक बार फिर

देश की सर्वशक्तिमान सैन्य व्यवस्था पर

तीखा हमला बोला है। उन्होंने सेना पर

"चर्वस्थित रूप से लोकतंत्र को नष्ट करने" और "

"चार्वातिक व्यवस्था को

अपने हितों के लिए हाइजैक करने" का

आरोप लगाया है।

अपने नवीनतम बयान, जो उनकी

कानूनी टीम के माध्यम से जारी किया

गया और पाकिस्तानी तथा अंतरराष्ट्रीय

मीडिया के कुछ हिस्सों में प्रकाशित हुआ

है, में खान ने आरोप लगाया कि सेना,

खासकर राष्ट्रपिण्डी में तेजाव शोने नेतृत्व,

ने "नियंत्रित सरकारों को माहज रबर

स्ट्रैम्प बना दिया है" और पाकिस्तान के

लोकतंत्र को "एक नियंत्रित शासन में

बदल दिया है, जो एपोल कंट्रोल से

चलाया जा रहा है।"

विडियो में कि कभी इमरान को

सेना का पंसंदा उम्मीदवार माना जाता

- यह एक अजीबोरीब बात है कि 2018 के आम चुनाव में इमरान खान को पाकिस्तान में चुनेता उम्मीदवार माना जाता था और वे चुनाव जीते तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, सेना की पूरी मदद से।
- पर, 2022 तक इमरान खान व सेना के रिश्ते खट्टे हो चुके थे, विदेश नीति व सेना के उच्च अफसरों की नियुक्ति के सवाल पर तथा इमरान का खुला आरोप है कि सेना ने प्रायोजित अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको हटवा दिया था।
- इमरान खान इसी लय में यह साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सच्चा प्रजातंत्र तभी संभव है, जब सेना "बैरेक्स" में लौट जाए और अपनी भूमिका संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं तक ही सीमित रखे।
- इमरान खान का यह "हृदय परिवर्तन" कैसे हुआ और क्यों हुआ?
- इमरान खान पहले तो सेना की मदद से प्र.मंत्री बने थे और अब सेना की भूमिका को ही बदलना चाहते हैं।
- पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक स्थिति का गहराई से विश्लेषण करने वाले प्रतिष्ठित विचारक के अनुसार, पहले तो इमरान खान ने सेना को मजबूत किया व सेना की भूमिका का पूर्ण समर्थन किया और पाकिस्तान की राजनीति में सेना को पैर जानाने का पूरा पौका दिया और अब वे पूर्णतया सेना की भूमिका को पाकिस्तान की गढ़बड़ स्थिति के लिए जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं।

था, विशेष रूप से 2018 के विवादास्पद पाकिस्तान

तहीकी-ए-इंसाफ

आम चुनाव में, जिसमें उनकी पार्टी (पीटीआई) को सत्ता मिली थी।

2022 में विदेश नीति और सैन्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाभियोग चलेगा
जस्टिस वर्मा पर?

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मई। राष्ट्रदूत न्यायालय के जस्टिस व्यवस्था पर वर्जित वर्मा पर जल्द ही महाभियोग की तलबाव लटक सकती है। महाभियोग संसद में लाया जाएगा, जो किसी मौजूदा न्यायाधीश को हठाने का एकमात्र उपाय है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक

गोपनीय जाँच रिपोर्ट, जिसे इंडिया

राज्यसभा की आठ रिक्त सीटों पर चुनाव है, 19 जून को

इन चुनावों का गणना की दृष्टि से कुछ भारी असर नहीं पड़ेगा, राज्यसभा के राजनीतिक समीकरणों पर, लेकिन, एनडीए को थोड़ा नुकसान तो होगा ही इस चुनाव से

C
M
Y
K

C
M
Y
K

■ सुप्रीम कोर्ट की गोपनीय जाँच रिपोर्ट, जिसे इंडिया टूडे ने खोज निकाला है, के अनुसार, जस्टिस वर्मा अपने आवास पर आग लगाने के बाद मिले जले हुए नोटों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके, इसलिए उन पर संसद में महाभियोग चलाने की कार्यवाही की जा सकती है।

ने खोज निकाला है, में न्यायाधीश के घर के अंदर जली हुई नकदी के देने के देने पर कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं मिला है। गलत आवरण के गंभीर आरोपों, संदिग्ध आग लगाने के द्वारा रात के फोन और दिल्ली पुलिस द्वारा कानूनी अड़चनें बताए जाने के साथ, अब केन्द्र और संसद पर दबाव है।

मानवन सत्र नजदीक आ रहा है,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मई। राज्यसभा की

8 सीटों पर 19 जून को चुनाव होगा, इनमें से 6 सीटें तमिलनाडु से हैं

और 2 असम से, हालांकि इनके नियोजितों

से राज्यसभा के सेवा भूलान पर खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सत्रालूप एनडीए को मामूली झटका लग सकता है, खासकर तमिलनाडु से जहाँ बलते राजनीतिक समीकरणों ने गुकाना हो सकता है।

तमिलनाडु की 234 संसदीय

विधानसभा में द्रुमुक के नेरुल वाले

गठबंधन का बहुमत है। उनके पास

133 सीटें हैं, उसे कांग्रेस (17 सीटें)

वोट चाहिए और वामपंथी दल (4 सीटें)

कोई विधायिका को उनका समर्थन हो सकता है।

तमिलनाडु के 234 संसदीय

विधानसभा के द्रुमुक के नेरुल वाले

गठबंधन का बहुमत है। उनके पास

133 सीटें हैं, उसे कांग्रेस (17 सीटें)

वोट चाहिए और वामपंथी दल (4 सीटें)

कोई विधायिका को उनका समर्थन हो सकता है।

इसके बाद एनडीए को जल्दी ही

मिलेगा। आजपाएं एनडीए की

सीटों में यह सीटें एनडीए की

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्तीड़क चाबुक बन जाती हैं। -शेक्सपियर

कंवरलाल मीणा की विधायकी समाप्त हो गई, किन्तु कारावास की सजा के कारण अयोग्य होने से सीट रिक्त होने का आदेश सही प्रतीत नहीं होता

रा

जस्थान विधानसभा के अन्ता (बांग) जिले से विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता, विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने दिनांक 1.5.2025 से समाप्त कर दी थी और अन्ता विधान सभा सीट रिक्त घोषित की है।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कंवरलाल मीणा विधायक को दोष सिद्ध की तारीख से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्य होना माना है। इसके विरुद्ध एक फौजदारी केस था, जिसके तथ्य हैं कि मीणा ने 3 फरवरी 2005 को मनोहर थाना (जिला ज्ञालावाड़) क्षेत्र में उपचुनाव के समय एसडीएम राम निवास मेहना को पिटोल दिखाकर बोटों की पुनः मतगणना कराने के लिये धमकी दी थी और लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 171(ई) का अप्राप्य किया था। इस केस में लोअर कोर्ट ने (दायरा कोर्ट ने) सन 2018 में बरी कर दिया था; किन्तु अप्रील अदालत (एर्फीटी) ने 2020 में उनकी अपील खारिज की और उन्हें तीन वर्ष की सजा दी। कंवरलाल मीणा को अप्राप्य उन पर तागाया था उस पर दोष सिद्ध माना। कंवरलाल मीणा ने एडीजे के कन्वीनेशन के विरुद्ध राजसभा उच्च न्यायालय में शरण ली। उच्च न्यायालय ने प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उच्च न्यायालय के विरुद्ध उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील प्रस्तुत की है, वह भी खारिज हो चुकी है। मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध रियू प्रियंशन दायर की है जिस पर 15 जुलाई 2025 को अपील कोर्ट ने अस्वीकार कर दी है।

अपील आदि के दौरान कोटस सज्ज स्थिति की थी; किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 1 मई, 2025 को कंवरलाल मीणा की याचिका खारिज कर दी। इससे यह अर्थ निकाला गया है कि सजा दिनांक 1 मई, 2025 से प्रभावशाली हो गई। किन्तु विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कंवरलाल मीणा की धर्म घटना के बाद बने कार्यकारी सत्ता के लिए लड़ने वाला युद्ध प्रियंशन के बाद विवाह कर दिया था उस पर दोष सिद्ध माना। कंवरलाल मीणा ने एडीजे के कन्वीनेशन के विरुद्ध राजसभा उच्च न्यायालय में शरण ली। उच्च न्यायालय ने प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उच्च न्यायालय के विरुद्ध उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील प्रस्तुत की है, वह भी खारिज हो चुकी है। मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध रियू प्रियंशन दायर की है जिस पर 15 जुलाई 2025 को अपील कोर्ट ने अस्वीकार कर दी है।

नेता प्रतिपक्ष दीकरम जूली ने विधान सभा के विरुद्ध देरी का आरोप लगाया है किन्तु विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी समाप्ति किये जाने को न्याय और सत्य की जीत बताया है और इसे कांग्रेस के संविधान बचाओ आन्दोलन की जीत कहा है। कांग्रेस के प्रेदेश अध्यक्ष भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी इस घटना को सल्ल की जीत कहा है और संविधान को सोचेंपरी स्वीकारा है। अध्यक्ष देवनानी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि 'वे नहीं चाहते कि वे एसा राजनीतिक घटना पलट लायें'। उन्होंने अपील पीढ़ा अभियन्त्र करते हुए कहा है कि वे इसके बाबत नये चुनाव की आदेश सप्ताह के लिए तारीख दिनांक 1 मई 2025 से अयोग्य घोषित किया है। विधानसभा की सीट रिक्त हो गई है। इसके बाबत नये चुनाव की आदेश सप्ताह के लिए तारीख दिनांक 1 मई 2025 को अस्वीकार कर दी है।

जैसे ऊपर कहा है कंवरलाल मीणा की विधायकी समाप्ति को तारीख से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत निरहित (अयोग्य कुनैनसपल) किया है। उनका कन्वीनेशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 171(1)(ई) के तहत अपराध (वर्मिदबम) करित करने के कारण हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 घोषित करती है कि विधिकी का कन्वीनेशन (दोष सिद्ध) होता है तो उसे विधायिकों की सदस्यता से अयोग्य माना जावेगा। यदि उसका सजा 2 वर्ष की हो तो उसे अयोग्य हो और वह अयोग्यता कन्वीनेशन की तारीख से होगी और अयोग्यता 6 वर्ष की होगी। अयोग्यता का प्राप्तमूलक करते हुए कहा है कि वे इसके बाबत प्राप्तमूलक करते हुए अप्राप्य लगाया जाएं। उन्होंने अपील पीढ़ा अभियन्त्र करते हुए कहा है कि वे इस मामले में राजनीतिकण का निन्दनीय मानते हैं। कंवरलाल मीणा ने तीन साल की सजा के बाद दिनांक 21 मई, 2025 को कोर्ट से सरेन्डर किया। विधानसभा के बुलेटिन के हिस्से उनकी विधायकी समाप्ति की थी।

जैसे ऊपर कहा है कंवरलाल मीणा की विधायकी समाप्ति को तारीख से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्य होना माना है। उसके विरुद्ध एक फौजदारी केस था, जिसके तथ्य हैं कि विधायिकों की सदस्यता से अयोग्य माना जावेगा। यदि उसका सजा 2 वर्ष की हो तो उसे अयोग्य हो और वह अयोग्यता कन्वीनेशन की तारीख से होगी और अयोग्यता 6 वर्ष की होगी। अयोग्यता का प्राप्तमूलक करते हुए कहा है कि वे इस मामले में राजनीतिकण का निन्दनीय मानते हैं। कंवरलाल मीणा ने तीन साल की सजा के बाद दिनांक 21 मई, 2025 से समाप्त किया।

जैसे ऊपर कहा है कंवरलाल मीणा की विधायकी समाप्ति को तारीख से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्य होना माना है। उसके विरुद्ध एक फौजदारी केस था, जिसके तथ्य हैं कि विधायिकों की सदस्यता से अयोग्य माना जावेगा। यदि उसका सजा 2 वर्ष की हो तो उसे अयोग्य हो और वह अयोग्यता कन्वीनेशन की तारीख से होगी और अयोग्यता 6 वर्ष की होगी। अयोग्यता का प्राप्तमूलक करते हुए कहा है कि वे इस मामले में राजनीतिकण का निन्दनीय मानते हैं। कंवरलाल मीणा ने तीन साल की सजा के बाद दिनांक 21 मई, 2025 को कोर्ट से सरेन्डर किया। विधानसभा के बुलेटिन के हिस्से उनकी विधायकी समाप्ति की थी।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कंवरलाल मीणा विधायकी समाप्ति को तारीख से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्य होना माना है। उसके विरुद्ध एक फौजदारी केस था, जिसके तथ्य हैं कि विधायिकों की सदस्यता से अयोग्य माना जावेगा। यदि उसका सजा 2 वर्ष की हो तो उसे अयोग्य हो और वह अयोग्यता कन्वीनेशन की तारीख से होगी और अयोग्यता 6 वर्ष की होगी। अयोग्यता का प्राप्तमूलक करते हुए कहा है कि वे इसके बाबत प्राप्तमूलक करते हुए अप्राप्य लगाया जाएं। उन्होंने अपील पीढ़ा अभियन्त्र करते हुए कहा है कि वे इस मामले में राजनीतिकण का निन्दनीय मानते हैं। कंवरलाल मीणा ने तीन साल की सजा के बाद दिनांक 21 मई, 2025 को कोर्ट से सरेन्डर किया। विधानसभा के बुलेटिन के हिस्से उनकी विधायकी समाप्ति की थी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्य होना माना है। उसके विरुद्ध एक फौजदारी केस था, जिसके तथ्य हैं कि विधायिकों की सदस्यता से अयोग्य माना जावेगा। यदि उसका सजा 2 वर्ष की हो तो उसे अयोग्य हो और वह अयोग्यता कन्वीनेशन की तारीख से होगी और अयोग्यता 6 वर्ष की होगी। अयोग्यता का प्राप्तमूलक करते हुए कहा है कि वे इसके बाबत प्राप्तमूलक करते हुए अप्राप्य लगाया जाएं। उन्होंने अपील पीढ़ा अभियन्त्र करते हुए कहा है कि वे इस मामले में राजनीतिकण का निन्दनीय मानते हैं। कंवरलाल मीणा ने तीन साल की सजा के बाद दिनांक 21 मई, 2025 को कोर्ट से सरेन्डर किया। विधानसभा के बुलेटिन के हिस्से उनकी विधायकी समाप्ति की थी।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने अपने नियन्त्रित दिनांक 01.01.2025 से एडीजे के नियन्त्रित किया। यह एक फौजदारी केस था, जिसके तथ्य हैं कि विधायिकों की सदस्यता से अयोग्य माना जावेगा। यदि उसका सजा 2 वर्ष की हो तो उसे अयोग्य हो और वह अयोग्यता कन्वीनेशन की तारीख से होगी और अयोग्यता 6 वर्ष की होगी। अयोग्यता का प्राप्तमूलक करते हुए कहा है कि वे इसके बाबत प्राप्तमूलक करते हुए अप्राप्य लगाया जाएं। उन्होंने अपील पीढ़ा अभियन्त्र करते हुए कहा है कि वे इस मामले में राजनीतिकण का निन्दनीय मानते हैं। कंवरलाल मीणा ने तीन साल की सजा के बाद दिनांक 21 मई, 2025 को कोर्ट से सरेन्डर किया। विधानसभा के बुलेटिन के हिस्से उनकी विधायकी समाप्ति की थी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्य होना माना है। उसके विरुद्ध एक फौजदारी केस था, जिसके तथ्य हैं कि विधायिकों की सदस्यता से अयोग्य माना जावेगा। यदि उसका सजा 2 वर्ष की हो तो उसे अयोग्य हो और वह अयोग्यता कन्वीनेशन की तारीख से होगी और अयोग्यता 6 वर्ष की होगी। अयोग्यता का प्राप्तमूलक करते हुए कहा है कि वे इसके बाबत प्राप्तमूलक करते हुए अप्राप्य लगाया जाएं। उन्होंने अपील पीढ़ा अभियन्त्र करते हुए कहा है कि वे इस मामले में राजनीतिकण का निन्दनीय मानते हैं। कंवरलाल मीणा ने तीन साल की सजा के बाद दिनांक 21 मई, 2025 को कोर्ट से सरेन्डर किया। विधानसभा के बुलेटिन के हिस्से उनकी विधायकी समाप्ति की थी।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने अपने नियन्त्रित दिनांक 01.01.2025 से एडीजे के नियन्त्रित किया। यह एक फौजदारी केस था, जिसके तथ्य हैं कि विधायिकों की सदस्यता से अयोग्य माना ज

